



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185]
No. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1987/चैत्र 20, 1909
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1987/CHAITRA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में,
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

गा. का. नि. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, वण औद्योगिक कंपनी
(विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 की
उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पाठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण और अन्य सदस्यों के
वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें नियम, 1987 है।

(2) ये 15 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न
हो,—

- (क) "अधिनियम" से वण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधि-
नियम, 1985 (1986 का 1) अभिप्रेत है,
- (ख) "अपील प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है,
- (ग) "अध्यक्ष" से अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है,
- (घ) "सदस्य" अपील प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है।

3. वेतन:—(1) अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन
अनुभोग्य है, वह वेतन प्राप्त करेगा।

(2) सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन अनुभोग्य है,
वह वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में जो
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त
हुआ है या सरस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में जो
किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या कोई

का सदस्य रह चुका है या जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या अन्य रूप में सेवानिवृत्ति प्रभुविधाय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन तथा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में निवेशन के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति प्रभुविधाय यदि कोई है, को सकल राशि कम कर दी जाएगी।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता :—(1) अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता प्राप्त करेगा।

(2) सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता प्राप्त करेगा।

5. छुट्टी :—(1) कोई व्यक्ति जो अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होता है वह निम्नलिखित छुट्टी का हकदार होगा :—

(1) सेवा के प्रत्येक संपूर्ण कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए तीस दिन के हिसाब से उपाजित छुट्टी :

परन्तु यह कि छुट्टी लेखा में प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन की उपाजित छुट्टी, अग्रिम के रूप में दो हिस्सों में जमा की जाएगी :

परन्तु यह और कि पूर्व अर्ध वर्ष की समाप्ति पर जमा उपाजित छुट्टी अगले अर्ध वर्ष में इस शर्त के अधीन अग्रणी की जाएगी कि इस प्रकार अग्रणी छुट्टी तथा अर्ध वर्ष में जमा छुट्टी का योग एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगा।

(2) चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर या निजी कार्य होने पर सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन के हिसाब से अर्द्धवेतन छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन, उपाजित के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा।

(3) अर्द्धवेतन छुट्टी अध्यक्ष या सदस्य के विवेक पर पूर्ण वेतन छुट्टी के रूप में परिवर्तित की जा सकती, परन्तु यह तब जब यह चिकित्सीय आधार पर ली गई हो और इसके साथ किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सीय प्रमाणपत्र लगा हो।

(4) बिना वेतन और भत्तों के असाधारण छुट्टी, पदावधि की एक अवधि में एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक होगी।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी :—अध्यक्ष सदस्यों को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7. भविष्य निधि :—अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने विकल्प पर साधारण भविष्य निधि के लिए अभिदाय करने के लिए हकदार होगा और यदि वह ऐसा विकल्प देता है तो वह केन्द्रीय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

8. यात्रा भत्ता :—(1) जब अध्यक्ष दौरे पर या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकरण में पद ग्रहण करने के लिए या अपील प्राधिकरण में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने स्वगृह को जाने के लिए की गई यात्रा भी आती है) होगा तो वह यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी चीजबस्त के परिवहन के लिए और अन्य ऐसे मामलों में उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर, जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते नियम, 1959 में विहित है, हकदार होगा।

(2) जब कोई सदस्य दौरे पर या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकरण में पदग्रहण करने के लिए या अपील प्राधिकरण में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने स्वगृह को जाने के लिए की गई यात्रा भी है) होगा वह यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी चीजबस्त के परिवहन के लिए और अन्य ऐसे मामलों में उन्हीं मापमानों और उन्हीं दरों पर, जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विहित है हकदार होगा।

9. छुट्टी यात्रा रियायत :—(1) अध्यक्ष, उन्हीं दरों और उन्हीं मापमानों पर छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार होगा, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लागू हैं।

(2) अन्य सदस्य उन्हीं दरों और उन्हीं मापमानों पर छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार होंगे, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू हैं।

10. वास सुविधा :—(1) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपील प्राधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर अनुज्ञाति फीस के संदाय पर दिल्ली में तैनात केन्द्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारियों को अनुज्ञेय टाइट की साधारण पूरा वास सुविधा में पदीय आवास के उपयोग के लिए, यदि उपलब्ध हो, प्राप्त होगा।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि से आगे पदीय आवास की अधिमोग में रुकता है तो वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुज्ञाति फीस या शास्तिक किराया संदाय करने के लिए दायी होगा और वह केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू नियमों के अनुसार बेदखली के लिए दायी होगा।

11. सवारी की सुविधा :—(1) अध्यक्ष और सदस्य एक स्टाफ कार और प्रति मास की एक सौ पचास लिटर पेट्रोल या प्रतिमास पेट्रोल की वास्तविक खपत का इन में से जो भी कम हो, हकदार होगा।

12. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएं :—अध्यक्ष या अन्य सदस्य, चिकित्सीय उपचार और अस्पताल संबंधी सुविधाओं के लिए अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में उपबंधित के अनुसार हकदार होंगे और ऐसे स्थानों में, जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, वहां अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय सेवा चिकित्सीय परिवर्तन नियमों में उपबंधित के अनुसार सुविधाओं के लिए हकदार होंगे।

13. अवशिष्टीय उपबंध :—अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को सेवा शर्तों से संबंधित ऐसे मामलों में से जिनकी बाबत कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामला केन्द्रीय सरकार को उसके दिनिर्णय के लिए निविष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनियम्य अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के लिए आवश्यक होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th April, 1987

NOTIFICATION

GSR 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and other Members) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the 15th day of April, 1987.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986);
- (b) "Appellate Authority" means the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction constituted under section 5 of the Act;
- (c) "Chairman" means the Chairman of the Appellate Authority;
- (d) "Member" means a Member of the Appellate Authority;

3. Pay.—(1) The Chairman shall receive pay as admissible to a judge of the Supreme Court.

(2) A Member shall receive pay as admissible to a judge of a High Court;

Provided that in the case of an appointment of a person as a Chairman who has retired as a judge of the Supreme Court or a High Court or in the case of an appointment of a person as a Member who has retired as a judge of a High Court or had been a Member of the Board, or has retired from service under the Central Government or a State Government, and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity employers contribution to the contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairman or Member shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance.—(1) The Chairman shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to a judge of the Supreme Court.

(2) A Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to a judge of a High Court.

5. Leave.—(1) A person, on appointment in the Appellate Authority as Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows:

- (i) Earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service or a part thereof: Provided that the leave account shall be credited with earned leave, in advance, in two instalments of fifteen days each on the 1st day of January and July of every calendar year:

Provided further that earned leave at the credit at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus credit for the half year do not exceed one hundred and eighty days.

- (ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;
- (iii) Leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairman or a Member provided, it is taken on medical grounds, and is supported by a medical certificate by a competent medical authority;
- (iv) Extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

6. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to a Member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

7. Provident Fund.—The Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting, shall be governed by the provisions of the Central Provident Fund (Central Services) Rules.

8. Travelling Allowances.—(1) The Chairman while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Authority or on the expiry of his term with the Appellate Authority to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are prescribed in the Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1959.

(2) A Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Authority or on the expiry of his term with the Appellate Authority to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances daily allowance transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Traveling Allowance) Rules, 1956.

9. Leave travel concession.—(1) The Chairman shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a judge of the Supreme Court. (2) A Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and the same scales as are applicable to a judge of the Delhi High Court.

10. Accommodation.—(1) Every person appointed to the Appellate Authority as a Chairman or a Member shall be eligible, subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay and stationed at Delhi on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where a Chairman or a Member occupies an official residence beyond permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and he will be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government servants.

11. Facility of conveyance.—The Chairman and the Members shall be entitled to a staff car and one hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol per month, whichever is less.

12. Facilities for medical treatment.—The Chairman or other Members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the Chairman and Members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules.

13. Residuary provisions.—Matters relating to the conditions of service of the Chairman or other Members with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairman or the other Members.

14. Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[F. No. 2(4)AA/87]

M. C. SATYAWADI, Jt. Secy.